भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 513

03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: जनजातीय किसानों द्वारा आमों की औनेपौने दामों पर बिक्री-

513. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओडिशा के रायगड जिले के काशीपुर ब्लॉक में आम की खेती करने वाले हजारों जनजातीय किसान शीतागारों की अनुपलब्धता, मंडी खरीद की कमी, महंगे उर्वरकों और प्रसंस्करण इकाइयों की बिल्कुल अनुपलब्धता के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे उन्हें हर फसल के मौसम में औनेपौने दामों पर बिक्री के लिए मजबूर - होना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि संस्थागत खरीद के अभाव में निजी व्यापारी और बिचौलिए शोषणकारी कीमतों पर आम खरीद रहे हैं और जनजातीय किसानों को बाजार की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उचित आय से वंचित कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान रायगड जिले और काशीपुर ब्लॉक में स्वीकृत या संचालित शीतागारों विनियमित मंडियों, एफपीओ, मूल्य समर्थन योजनाओं और आम प्रसंस्करण इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पौने दामों पर बिक्री करने और शोषण -आम की खेती करने वाले जनजातीय किसानों को औने से बचाने के लिए शीतागार स्थापित करने, मंडी आधारित खरीद सुनिश्चित करने, प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और लाभकारी मूल्य की गारंटी देने के लिए सरकार की समयबद्ध कार्य योजना क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): इस संबंध में ओडिशा राज्य सरकार से भारत सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, ओडिशा राज्य सरकार ने बताया है कि सरकार रायगड़ा के काशीपुर ब्लॉक में आदिवासी आम किसानों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट लॉजिस्टिक और मौसमी चुनौतियों से अवगत है।

- **मौसमी मूल्य दबाव:** ढेंकानाल और अनुगुल जैसे जल्दी कटाई वाले जिलों के विपरीत, जहाँ आमों को बाजार में उच्च मूल्य मिलता है, रायगड़ा में आम की कटाई मौसम के अंत में होती है। यह अक्सर संयोगवश मार्केट सैचुरेशन और जल्दी बारिश की शुरुआत पर होता है।

- **गुणवत्ता पर प्रभाव:** देर से कटाई और जल्दी बारिश होने से अक्सर फलों पर "काले धब्बे"/दाग पड़ जाते हैं, जिससे उच्च स्तरीय निर्यात बाजारों के लिए आवश्यक अच्छी

गुणवत्ता कम हो जाती है और निजी व्यापारियों के साथ किसानों की मोलभाव करने की शक्ति कम हो जाती है।

- **हस्तक्षेप:** इन जोखिमों को कम करने के लिए, सरकार फसलोपरान्त व्यवस्था और सामूहिक मोलभाव में सुधार लाने हेतु किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्तमान में, रायगड़ा जिले में 70 पंजीकृत एफपीओ हैं, जिनमें से 5 काशीपुर ब्लॉक में स्थित हैं।

(ग): ओडिशा राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान, रायगड़ा और गुनूपुर ब्लॉकों में कुल 5,600 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2 शीतागार, 7 सौर-आधारित शीत कक्ष और एक गर्म जल उपचार सुविधा के साथ-साथ दो विनियमित बाजार समितियां स्थापित की गई हैं।

(घ): बागवानी फसलों की मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए, भारत सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को फसलोपरान्त प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं। यह सहायता राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त उनकी अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अनुसार प्रस्तावों पर आधारित होती है। यह योजना मांग/उद्यमी संचालित है।

किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के अलावा, सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्यान्वित करती है, जिसका उद्देश्य कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद करना है जो जल्दी खराब होने वाली प्रकृति के होते हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन उत्पादों के उत्पादकों को बंपर फसल होने पर, आवक के चरम समय में, जब कीमतें आर्थिक स्तर से नीचे गिरने लगती हैं, मजबूरन बिक्री करने से बचाना है। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, जो इसके कार्यान्वयन में होने वाले किसी भी नुकसान का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) वहन करने के लिए तैयार है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2024-25 सीजन से बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत भावान्तर भुगतान (पीडीपी) का एक नया घटक शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जल्दी खराब होने वाले फसलों के किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जाएगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास फसल की वास्तविक खरीद करने या किसानों को एमआईपी और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर भुगतान करने का विकल्प है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) पर आमों की खरीद को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर तब मंजूरी देता है जब बाजार मूल्य एमआईपी से नीचे चला जाता है।

*****